



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931

No. 658]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय, सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

विषय : कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड के आयातों के बारे में रक्षोपाय जांच-अंतिम जाँच परिणाम ।

सा.का.नि 824(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम, 1997 को ध्यान में रखते हुए :—

प्रक्रिया

1. सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत भारतीय पेपर विनिर्माता एसोसिएशन, पीएचडी हाउस (चौथा तल), 4/2 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया (एशियन खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016 के सहयोग से (1) आईटीसी लि., पेपर बोर्ड्स एवं स्पेशियलिटी पेपर्स डिविजन, 106 सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद-500003, आंध्र प्रदेश, (2) बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि., फर्स्ट इंडिया प्लेस, टावर सी, महारौली, गुडगाँव रोड, गुडगाँव (हरियाणा)-122001 और (3) जे के पेपर लि., नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें भारत में मुख्य रूप से वर्जिन केमिकल पल्प से निर्मित कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के बढ़े हुए आयातों से होने वाली गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति के सतत खतरे के विरुद्ध कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए भारत में मुख्य रूप से वर्जिन केमिकल पल्प से निर्मित कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के बढ़े हुए आयातों पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया गया था ।
2. इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है, दिनांक 20 अप्रैल, 2009 को सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत भारत में कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जाँच की शुरुआत की

अधिसूचना जारी की गई थी और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

3. नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से निर्यातक देशों की सरकारों को सूचना की प्रति भेजी गई थी। सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकार जिनकी सूची निम्नानुसार है, को जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रति भेजी गई थी:-

**घरेलू उत्पादक:**

- i आईटीसी लि०- पेपर बोर्ड्स एवं स्पेशियलिटी पेपर्स डिविजन, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश
- ii बल्लरपुर इंडस्ट्रीज लि०, गुडगाँव, हरियाणा
- iii जेके पेपर लि०, नई दिल्ली

**घरेलू उत्पादक एसोसिएशन**

- i भारतीय पेपर विनिर्माता एसोसिएशन, पीएचडी हाउस, (चौथा तल), 4/2 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया (एशियन खेल गांव के सामने), नई दिल्ली-110016

**आयातक एवं प्रयोक्ता**

- i चिमनलाल फाइन पेपर प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र।
- ii इंफिनिटी इंडस्ट्रीज प्रा.लि., मुम्बई, महाराष्ट्र।
- iii अजंता ऑफसेट और पैकेजिंग लि. फरीदाबाद, हरियाणा।
- iv एयरो एक्सपोर्ट, मानेसर, गुडगाँव, हरियाणा।
- v न्यूटेक फोटोलिथोग्राफिक, नई दिल्ली।
- vi रेपलिका प्रेस प्रा.लि., हरियाणा।
- vii ब्रिजवासी प्रिंटर्स, नई दिल्ली
- viii राजाराम, चावड़ी बाजार, दिल्ली
- ix शोबा कार्ड्स, दरियागंज, नई दिल्ली
- x सुनेजा संस, चावड़ी बाजार, दिल्ली

**निर्यातक एवं विदेशी उत्पादक**

- i गोल्ड ईस्ट पेपर (जियांग्सु) कं. लि., 8 जिंग गैंग डोंग आरडी, दागांग, जियांग्सु, चीन 212132
- ii एपीपी-इंडोनेशिया, पीटी. पिंडो डेली पल्क एंड पेपर मिल्स, प्लाजा बी 11-मेनारा II, 9वाँ तल, जेएल एमएच थामरिन सं. 51, जकार्ता

- iii एसएपीपीआई: मैसर्स सप्पी डॉएशलैंड, जीएमबीएच बर्लिनर ऐली, 14डी-30175 हेनोवर, द्वारा सप्पी सिंगापुर पीटीई ऐनसनरोड- 079903
- iv स्टोरा एनसो ओईज, पोस्ट बॉ. सं. 309, एफआई-00101, हेल्सिकी, फिन्लैण्ड
- v चेनमिंग पेपर कं.लि., नानचान चाँगबेई इकोनामिक एंड टैक्नीकल डवलपमेंट जोन, जियाँगसी, चीन
- vi मैसर्स स्टोरा एनसो शुझोऊ पेपर कं.लि., 600 बिन्हे रोड शुझोऊ न्यू डिस्ट्रिक्ट, शुझोऊ सिटी, चीन
- vii एम-रियल कॉर्पोरेशन, पोस्ट बॉक्स 20, मैट्सा 02020, फिन्लैण्ड
- viii मूरिम पेपर कं., 281-1 सैंगयाँग-डाँग, जिन्जू-एसएल, 660903, दक्षिण कोरिया
- ix हांगकांग पेपर विनिर्माण कं.लि., # 14, आईएमजी वाँग बिल्डिंग, मिग्यून-डाँग, सियोल, दक्षिण कोरिया
- x हंसोल पेपर कं.लि. 22वाँ तल, हंसोल बिल्डिंग, 736-1, योकसाम-डाँग, गंगनाम-गु-सियोग, 135-080, दक्षिण कोरिया
- xi गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग (हांगकांग) कं.लि., यूनिट 501-504ए, एम्पायर सेंटर, 68 मोडी रोड, टी सिमशा सुई, पूर्वी हांगकांग
- xii कोवा कं.लि., 6-29 निशिकी 3-कॉम नाका-कू नागोया, जापान
- xiii वाइटल सोल्यूशन्स पीटीई लि., सिंगापुर 069532
- xiv डाईई पेपर (एसए) पीटीई लि0, 3, शेंटन वे, # 11-08 शेंटन हाउस, सिंगापुर
- xv सेल मार्क एशिया पीटीए लि., 47 स्कॉट्स रोड, # 12-01, गोल्डबेल टॉवर्स, सिंगापुर

#### निर्यातक राष्ट्र

- i नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन गणराज्य
  - ii नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से जकार्ता
  - iii नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से सिंगापुर
  - iv नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से जापान
  - v नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से हांगकांग
  - vi नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से कोरिया गणराज्य
  - vii नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से फिनलैंड
4. निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने के लिए समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए समय-विस्तार हेतु अनुरोध की अनुमति दी गई थी और संबंधित पक्षकारों को तदनुसार सूचित किया गया था ।

5. जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करने के बाद 24 अप्रैल, 2009 को प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए गए थे। प्रारंभिक जाँच परिणामों के आधार पर यह देखा गया था कि कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के बड़े हुए आयातों से कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई थी। महानिदेशक (रक्षोपाय) ने कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के घरेलू उत्पादकों के हित की सुरक्षा तथा मुख्य रूप से वर्जिन केमिकल पल्प से निर्मित एवं उप शीर्ष सं. 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200, और 48109900, के अंतर्गत वर्गीकृत कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के भारत में आयातों पर लगाए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम रक्षोपाय शुल्क के रूप में 20% (बीस प्रतिशत) यथामूल्य की दर से रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी।
6. दिनांक 11 सितम्बर, 2009 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी जिसके लिए 12 अगस्त, 2009 को सूचना भेजी गई थी। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुए सभी हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों को सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अभ्यावेदन या खंडन यदि कोई हो, के रूप में प्रस्तुत किए गए सभी विचारों की जाँच की गई थी और उपयुक्त निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया है।
7. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोध या खंडन यदि कोई हो, के रूप में प्रस्तुत किए गए सभी विचारों की जाँच की गई थी और उपयुक्त निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया है। चूंकि अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों की संख्या बहुत अधिक है, अतः संक्षिप्तता की वजह से हितबद्ध पक्षकारों के विशिष्ट नामों का उल्लेख किए बिना उनके विरोधों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर उपयुक्त स्थानों पर विचार किया गया है।
8. घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का आवश्यक सीमा तक घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों के मौके पर दौरे द्वारा सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त लागत लेखाकार द्वारा लागत संबंधी आँकड़ों का भी सत्यापन एवं प्रमाणन किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतर सार्वजनिक फाइल में रखा गया है।

भारत में घरेलू उत्पादकों के विचार

आवेदकों ने निम्नानुसार निवेदन किया है

9. घरेलू उद्योग ने कहा है कि एचएसएन तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200, और 48109900, के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद को "विचाराधीन उत्पाद" माना जाना चाहिए ।
10. कम कीमत के साथ आयातों में वृद्धि हो रही है जिससे उन्हें बाजार हिस्सा गँवाना पड़ा है ।
11. निर्यातक देशों में माँग में कमी से उन देशों के विनिर्माता निर्यातों पर भारी छूट के जरिए अपनी बेशी वस्तुसूची के निपटान हेतु बाध्य हुए हैं और यही आयातों में अचानक वृद्धि का कारण है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और उसके लिए गंभीर क्षति का खतरा बना हुआ है ।
12. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर आय में कमी आई है ।
13. कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से सार्वजनिक हित को क्षति नहीं होगी क्योंकि भारत में कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड की कीमतें कमोबेश स्थिर हैं ।
14. वर्ष 2005-06 की बजट घोषणा के अनुसार पेपर उद्योग में क्षमता वर्धन को प्रोत्साहित करना भारत सरकार की नीति है ताकि भारत आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सके ।
15. उद्योग के वैश्विक आकार की तुलना में भारतीय पेपर उद्योग का आकार बहुत ही छोटा है । विदेशी उत्पादकों द्वारा भारत भेजा जाने वाला पेपर का एक छोटा हिस्सा भी भारतीय पेपर उद्योग को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है ।
16. पेपर उद्योग एक श्रम गहन उद्योग है । उद्योग से 1.2 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 3.4 लाख व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार अर्थात् कुल 4.6 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है ।
17. कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड खण्ड से बागान कार्यकलापों के जरिए 48750 परिवारों अर्थात् मोटे तौर पर 2.5 लाख व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है ।

18. कागज उद्योग दीर्घ परिपक्वता अवधि के साथ एक अत्यधिक पूंजी गहन उद्योग है। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. (बीआईएलटी) तथा जेके पेपर लि. ने पिछले दो वर्षों में कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड खण्ड में क्रमशः 1,90,000 मी. टन तथा 60,000 मी. टन की अतिरिक्त क्षमताओं को जोड़ा है।
19. वैश्विक रूप से कागज उद्योग ने पेपर के उत्पादन तथा कृषि समुदायक बीच एक संपर्क स्थापित किया है जिससे कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ी पूंजी के निवेश होने लगा है।
20. कागज उद्योग प्राथमिक रूप से ग्राम आधारित है, जिसका कृषि समुदाय के साथ गहरा संबंध है, वर्षों के दौरान यह अपने पूर्ववर्ती वन-आधारित उद्योग के स्वरूप से कृषि आधारित उद्योग के रूप में उभरा है।
21. कोयला, जो कागज के विनिर्माण हेतु अपेक्षित वाष्प एवं विद्युत के संवर्धन हेतु प्रमुख ईंधन है, विदेशी उत्पादकों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध है।
22. विदेशी मिलों की क्षमता अत्यधिक विशाल हैं और भारतीय मिलों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती है।
23. कागज उद्योग, ग्रामीण भारत में रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए फैक्टरी के निकट कृषि वानिकी को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।
24. धनी एवं विकसित देशों में कृषकों एवं कृषि व्यापार निगमों को बड़ी कृषि सब्सिडियाँ प्रदान की जा रही हैं। कागज उद्योग को संरक्षण देना एक तरह से लुग्दी काष्ठ रोपण में लगे भारतीय उपजकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करना है। अतः कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड पर रक्षोपाय शुल्क लगाना, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में है।
25. भारत में आबादी का लगभग दो-तिहाई कृषि पर निर्भर है, अतः कृषि समुदाय के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विश्व भर में कृषकों का हित अन्य किसी व्यक्ति के हित से बढ़कर है।
26. प्रिंटर्स एसोसिएशन का यह आरोप कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद खराब गुणवत्ता का है आधारहीन है। यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड विश्वस्तरीय गुणवत्ता का है और इसे भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। सभी इकाइयाँ आईएसओ प्रमाण पत्र धारक हैं।

27. वर्ष 2008-09 के प्रथम नौ महीनों की हाल की अवधि में संबद्ध वस्तुओं के मासिक आयात वर्ष 2007-08 के 11057 मी. टन से बढ़कर 16872 मी. टन प्रति माह हो गए; जो वर्ष 2007-08 की तुलना में 50% से अधिक है। अतः कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड के आयातों में समग्र घरेलू बाजार की तुलना में समग्र अर्थों में तथा तुलनात्मक अर्थ में भी वृद्धि हुई है।

28. सितम्बर, 2008 के बाद, जब स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात कीमत में अत्यधिक गिरावट प्रदर्शित हुई है।

29. आयात कीमतों में गिरावट आने के कारण भारतीय घरेलू उद्योग के कुछ विनिर्माताओं को आयोजित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किलों के कारण अपने संयंत्र बंद करने पड़े हैं।

30. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता तथा लगाई गई पूंजी पर आय कम हुई है। संयंत्रों की लाभप्रदता एवं लगाई गई पूंजी पर आय में अत्यधिक गिरावट देखी गई है।

31. ग्लोबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के अग्रणी सूचना प्रदाता आरआईएसआई में अपने आउटलुक ब्रीफिंग्स 2009 में कागज उद्योग के कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड खण्ड के लिए निम्नलिखित अभूतपूर्व पूर्वानुमान लगाए हैं अर्थात् विकसित देशों में माँग में गिरावट, कोटेड पेपर के आयातों की कीमत प्रवृत्तियाँ कागज तथा बोर्ड की माँग वृद्धि इस दशक के पूर्वार्द्ध से भी अधिक कम होने की संभावना है।

32. चीन की केंद्रीय सरकार वर्ष 2010 तक कोर स्टेशन तथा कागज उद्योग के बीच एक संपूर्ण औद्योगिक शृंखला बनाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना चला रहा है। इसके परिणामस्वरूप चीन में वृहद क्षमता संवर्धन करने की घोषणा की गई है।

33. विभिन्न देशों में असमान मंदी से भारत में होने वाले आयातों में अचानक वृद्धि हुई है, जो अन्य देशों की तुलना में बेहतर है।

34. समायोजन योजना : 6.14 लाख मी. टन की वर्तमान क्षमता से लगभग 4.5 लाख मी. टन की घरेलू माँग की पूर्ति की जा सकती है। कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड की माँग में आगे होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए आगे क्षमता विस्तार करने की योजना बनाई गई है। हमने पहले ही एक विस्तृत दृढ़ एवं व्यापक समायोजन योजना (गोपनीय) प्रस्तुत की है जो कारगर कृषि वानिकी उपायों के जरिए कच्ची सामग्री की लागतों को कम करने, ऊर्जा लागतों में तथा अन्य लागतों में कटौती करने पर केंद्रित

है। अपने वर्ष 2008-09 के क्षमता विस्तार में हमने पहले ही यह प्रदर्शित किया है कि हम समायोजन योजना के प्रति वचनबद्ध हैं।

### निर्यातकों के विचार

35. निर्यातक मै. एशिया पल्प एंड पेपर कं. लि., मै. सिनार मास पेपर (चीन) इन्वेस्टमेंट कं. लि., मै. पी. टी. फैब्रिक केरट्स जिवि कीमिया टीबीके, इंडोनेशिया, मै. पी टी पिंडो डेलि पल्प एंड पेपर मिल्स, इंडोनेशिया, मै. गोल्ड ईस्ट पेपर (जिंग्यासु) कं. लि., मै. गोल्ड ईस्ट ट्रेडिंग कं. लि. (चीन), मै. निंग्बो झोंगहुआ पेपर कं. लि. ने अपने परामर्शदाता के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं को विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

36. घरेलू उद्योग द्वारा बयान की गई, भारत में मौजूद प्रतिकूल स्थिति, रक्षोपाय शुल्क जांच की दृष्टि से असंगत है। इनमें से कोई भी कारण, आयातों में कथित वृद्धि का कारण नहीं है।

37. घरेलू उद्योग के निवेदनों में उन्होंने अपनी कथित क्षति के लिए अन्य कारणों का उल्लेख किया है आयातों में कथित वृद्धि का नहीं। बड़े हुए आयातों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण बड़े हुए आयातों को नहीं माना जाएगा।

38. घरेलू उद्योग अपनी इच्छानुसार जांच की अवधि में परिवर्तन करता रहा है। घरेलू उद्योग ने वस्तु सूची वृद्धि विश्लेषण के लिए पिछली तीन तिमाहियों को चुना है। जांच की अवधि की तुलना पूर्ववर्ती अवधियों के साथ नहीं की गई है। जैसा कि कुछेक अन्य मानदण्डों के लिए किया गया है।

39. आवेदक देश में कुल माँग का सही संगणन उपलब्ध करा पाने में असफल रहे हैं।

40. अप्रैल, सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर, 2008 के महीनों के आयातों में ह्रासकारी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है।

41. गिरती हुई आयात कीमतों के संबंध में आवेदकों का तर्क पूर्णतः गलत और अपूर्ण है। इस संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों हेतु कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।



42. घरेलू उद्योग की बिक्री एवं बाजार हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है। जैसा कि लिखित निवेदनों में पहले ही कहा गया है, यह स्पष्ट है कि बाजार हिस्से में कोई हानि नहीं हुई है।

43. मांग विश्लेषण कुल घरेलू बिक्री के संदर्भ में किया जाना चाहिए न कि केवल आवेदक घरेलू उद्योग के लिए।

44. “बढ़ते हुए बाजार के बावजूद घरेलू बाजार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार” नहीं था जिस देश में आवश्यक वस्तुओं के आयातों द्वारा पूरा किया गया था।

45. आवेदकों द्वारा पुनर्संरचना तथा अभूतपूर्व परिस्थितियों के संबंध में दिए गए वक्तव्य केवल अटकलबाजी एवं अनुमान मात्र हैं।

#### यूरोपीय पेपर उद्योग परिसंघ (सीईपीआई) के विचार

सीईपीआई यूरोप में स्थित यूरोपीय कागज उद्योग, जिसका हिस्सा कुल यूरोपीय कागज संबंधी क्षमताओं का लगभग 95% है, का प्रतिनिधित्व करता है। सीईपीआई ने इस मामले पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी हैं :

46. यद्यपि आयातों में कुछ वृद्धि हुई है तथापि, भारतीय प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए आंकड़े सही नहीं हैं। यूरोप से भारत में आने वाले पेपर एवं बोर्ड के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। यह हिस्सा जो वर्ष 2000 में 45% था, जो वर्ष 2007 में घटकर 34% रह गया था। ईयू आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्राधिकारियों द्वारा लक्षित भारत को पेपर ग्रेडों के निर्यात वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में 5% तक घट गए थे और वर्ष 2009 के प्रथम 5 महीनों में उनमें 30% के लगभग कमी दर्ज की गई है।

47. क्षति विश्लेषण अपूर्ण है। विश्लेषण, जांच अवधि के दौरान संपूर्ण वर्षों के लिए स्थापित प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए था। वर्ष 2008-09 हेतु क्षति विश्लेषण, उस वर्ष हेतु केवल 9 महीने की अवधि पर आधारित था।

48. शिकायत में दिए गए उत्पादन एवं बिक्री आंकड़ों में समग्र वृद्धि प्रदर्शित होती है और लाभ अब भी 5% के आसपास है जिससे गंभीर क्षति का पता नहीं चलता है।

49. किसी गंभीर क्षति (यदि कोई हो) के वास्तविक कारणों को स्पष्ट रूप से अभिज्ञात नहीं किया गया है। क्षति संबंधी विश्लेषण भी निश्चयात्मक नहीं है।

50. भारतीय घरेलू पेपर एवं बोर्ड उद्योग, भारतीय आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

51. सार्वजनिक हित जांच संबंधी विश्लेषण गलत है क्योंकि स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पाद एवं आयातित उत्पादों की प्रतिस्थापनीयता को कीमत तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है।

52. रक्षोपाय लागू करने से घरेलू उद्योग को एकाधिकारिक पद्धतियाँ अपनाने हेतु बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय प्रिंटर्स, प्रकाशकों एवं पैकर्स को अपर्याप्तता एवं उच्च कीमतों का सामना करना पड़ेगा।

#### यूरोपीय समुदाय के विचार

53. क्षति विश्लेषण न तो पूर्ण न वास्तविक और न ही निश्चयात्मक है और इसमें पारदर्शिता का अभाव है। संगत क्षति संकेतकों से संबंधित समग्र आंकड़ों को प्रकट नहीं किया गया है। प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए आंकड़ों की तुलनात्मकता को सुनिश्चित नहीं किया गया था। विश्लेषित अवधि में वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा वर्ष 2008-09 के केवल नौ महीने शामिल हैं।

54. उत्पादन एवं बिक्री में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और लाभ अब भी 5% के आसपास है, जो किसी गंभीर क्षति को इंगित नहीं करता है।

55. आयातों एवं कथित गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विश्लेषण त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण है।

#### एम रियल कॉर्पोरेशन, फिनलैंड के विचार :

एम रियल कॉर्पोरेशन, फिनलैंड ने अपने परामर्शदाता के माध्यम से निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं।

56. आयातों से संबंधित आंकड़े पूर्णतः गलत हैं। एक से अधिक समान उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद माना गया है जिससे विश्लेषण में गलती हुई है। आवेदक के आंकड़े को सही मानते हुए, उसके अनुसार घरेलू बाजार में आयातों के हिस्से में प्रतिवर्ष 3%

से कम वृद्धि हुई है जो उल्लेखनीय नहीं है। तथा समनुरूपी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उत्पादकों की बिक्री में 19% की वृद्धि हुई है। आयातों में किसी प्रकार का उछाल नहीं आया है।

57. एम रियल प्रोडक्ट्स, घरेलू पेपर बोर्ड की तुलना में गुणवत्ता एवं कीमत में पूर्णतः भिन्न हैं। एम रियल द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं और एम रियल द्वारा निर्यातित उत्पाद की किसी भी माँग को आयातों द्वारा ही पूरा किया जाता है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित कोई भी उत्पाद एम रियल के उत्पाद की विशेषताओं एवं विनिर्देशनों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। इन उत्पादों को गंभीर क्षति तो क्या किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है।

58. आवेदकों ने वैश्विक मंदी को आयातों में वृद्धि का कारण माना है, जो एक अभूतपूर्व परिस्थिति नहीं है। मंदी का उल्लेख आवेदक की वार्षिक रिपोर्टों में किया गया है। अब जैसा कि हमारे सरकार द्वारा घोषित किया गया है मंदी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और सभी आर्थिक मानदण्डों में मंदीकारी प्रवृत्ति से विपरीत स्थितियाँ प्रदर्शित हो रही हैं- अतः घरेलू उद्योग पर मंदी का कोई भी प्रभाव मौजूद नहीं है।

59. चूँकि आवेदकों का समग्र उत्पादन, कुल उत्पाद के 50% से कम है अतः वे घरेलू उद्योग नहीं बनते हैं। आईटीसी वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 के अनुसार, 5 अग्रणी विनिर्माताओं का हिस्सा, विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन में केवल 45% है और 100 से अधिक विनिर्माता मौजूद है। कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड के लिए, यदि उन्हें संयुक्त रूप से भी देखा जाए तो 3 आवेदकों ने अपने निवेदन में उत्पादन को केवल 314970 मी. टन दर्शाया है जबकि कुल घरेलू उत्पादन 1.24 मि. मी. टन है।

60. कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड समान उत्पाद नहीं हैं और उन्हें एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

**स्टोरा इन्सो ओवाईजे, ईयू के विचार**

स्टोरा इन्सोओवाईजे, ईयू ने अपने परामर्शदाता के माध्यम से निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं।

61. आवेदन में पारदर्शिता का अभाव तथा सटीक एवं समुचित सूचना का न होना।

62. आवेदकों ने सुनवाई के समय पर नए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।
63. स्टोरा इन्सों के कोटेड पेपर उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं और घरेलू उत्पादों के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं हैं ।
64. आयातों में कोई उछाल देखा नहीं गया है । क्षति, यदि कोई है, आयातों के कारण नहीं हुई है ।
65. कोटेड पेपर का आयात कम कीमतों पर नहीं किया जा रहा है ।
66. आवेदक द्वारा बाजार हिस्से, उत्पादन, मालसूचियों, क्षमता तथा लाभ के संबंध में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से प्रतीत होता है कि कोई “ गंभीर क्षति ” नहीं हुई है ।
67. यदि रक्षोपाय उपाय लागू किए जाते हैं तो भारतीय उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और शैक्षणिक प्रकाशनों की लागत में वृद्धि संभावित है ।
68. कोटेड पेपर बाजार में वैश्विक तथा भारतीय बाजार दोनों में निर्यात प्रवृत्ति कोई “ अप्रत्याशित घटनाक्रम ” नहीं है ।
69. आवेदन में कोई पुनःसंरचना अथवा समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है ।
70. रक्षोपाय उपायों के माध्यम से भारत में निगमित वानिकी की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता ।

### आयातकों के विचार

#### रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद के विचार

71. आधारभूत कच्चे माल अर्थात् लुग्दी और ईंधन की लागत घट गई है और अंतर्राष्ट्रीय कागज विनिर्माताओं ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को अंतरित कर दिया है । अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु मुद्रण करने वाले भारतीय मुद्रकों अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । रक्षोपाय उपाय अधिरोपित करने पर भारतीय मुद्रक अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त गँवा देंगे ।

72. निर्यातक अपना उत्पाद लागत से कम कीमत पर नहीं बेच रहे हैं। चूँकि कच्चे माल की लागत कम हो गई है, अतः अंतिम उत्पाद की कीमत भी कम हो गई है। यदि लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो निर्यातक अर्जित कर रहे हैं।

73. आयातित कागज का हिस्सा कुल घरेलू खपत का महज 1.13% है।

74. भारतीय कागज विनिर्माता आननी-अपनी वार्षिक विवरणियों के अनुसार लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास मासांत मालसूचियाँ भी नहीं हैं।

75. भारतीय मुद्रकों को आयातित कागज की आवश्यकता उसकी गुणवत्ता यथासमय उपलब्धता और भारत में कुछेक किस्मों का विनिर्माण न किए जाने के कारण होती है।

76. यदि कागज पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है, तो कागज की कीमत 20-25% बढ़ जाएगी। इससे पुस्तकें और भी महँगी हो जाएंगी। इससे पुस्तकालयों, पाठकों, लेखकों को नुकसान होगा। शिक्षा और भी महँगी हो जाएगी।

77. भारतीय मुद्रक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन उद्योग में एक मुद्रण केन्द्र होने का लाभ गँवा देगा।

78. रक्षोपाय उपाय मुद्रण और प्रकाशन उद्योग की कीमत पर भारत के कागज विनिर्माताओं का चयन करने में सहायक हो जाएँगे।

#### फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर एसोसिएशन के विचार :

फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर एसोसिएशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं :-

79. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग में उनका हिस्सा मात्र 38% है। यह आवेदन घरेलू उत्पादकों की ओर से आईटीसी लि., बल्लारपुर और जे के पेपर लि. ने प्रस्तुत किया है और यह आईपीएमए द्वारा समर्थित है। परन्तु आवेदन में दिए गए आंकड़े केवल तीन उत्पादकों से संबंधित हैं, जिनका कुल घरेलू उत्पादन में योगदान केवल 38% है।

80. आवेदन में दिए गए आंकड़े केवल तीन उत्पादकों से संबंधित हैं, जिनका उत्पादन में योगदान 38% है, न कि आईपीएमए के सभी सदस्यों से।

81. आवेदन में गोपनीयता की आड़ में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और नियम 7(2) के अनुसरण में इसे गोपनीय रखने का कोई वैध कारण भी नहीं दिया गया है।

82. आवेदन में समायोजन योजना भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो नियमावली का उल्लंघन है।

83. कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड अलग-अलग उत्पाद हैं और उनकी विनिर्माण प्रक्रिया एक स्थान नहीं है और ये अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा आसानी से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। इन्हें समान तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं माना जा सकता।

84. आवेदन गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे को सिद्ध करने में असफल रहा है क्योंकि आवेदन में ऐसे कोई आंकड़े/सूचना नहीं दी गई है जो किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम आयातों में भारी वृद्धि, बिक्री अथवा बाजार हिस्से में गिरावट, कच्चे माल की कीमतों में कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, क्षमता उपयोग में गिरावट, रोजगार के नुकसान अथवा वार्षिक रिपोर्टों में घाटे की द्योतक हो।

85. आवेदन कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने में असफल रहा है जो शुल्क की राशि का सुविचारित स्पष्टीकरण होता है।

86. आवेदकों को हुई क्षति वर्धित आयातों के कारण नहीं हुई है, बल्कि अन्य कारकों का इसका कारण माना जा सकता है।

87. आवेदकों ने कागज उद्योग में नियोजित लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

88. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से फेडरेशन के सदस्य और फेडरेशन से कागज की खरीद करने वाले व्यवसायी प्रभावित होंगे।

89. कृषि वानिकी उद्योग इस उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता, अपितु यह इस उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त एक निविष्टि मात्र है। कृषि वानिकी में लगे हुए किसानों की दुर्दशा पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह जांच कागज उद्योग पर केंद्रित है। रक्षोपाय जांच उत्पाद विशिष्ट है अर्थात् यह समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों से संबंधित है।

90. आवेदकों ने यह ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है कि 13,000/- करोड़ रुपए में से कितना निवेश अन्य उत्पादों के लिए किया गया है।

91. भारत में कच्चे माल का परिदृश्य वर्तमान जांच में प्रासंगिक नहीं है। भारत सरकार ने भारत में निगमित खेती को अनुमति न देने का नीतिगत निर्णय लिया है, जबकि विश्व भर की सरकारों ने इसकी अनुमति दे दी है। अतः इस दृष्टिकोण का सही समाधान रक्षोपाय शुल्क लागू करने के स्थान पर सरकार द्वारा अपनी नीति में बदलाव करना है।

92. ऊर्जा लागत आयातों की मात्रा पर निर्भर होती है। अतः उच्च ऊर्जा लागत के कारण हुई क्षति को वर्धित आयातों से नहीं जोड़ा जा सकता।

93. आवेदक द्वारा किया गया यह दावा भ्रामक है कि अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों के उपयोग एक समान हैं।

94. आवेदक के एक समर्थक-आईपीएमए द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि घरेलू उत्पादन में आवेदकों का योगदान केवल 38% है।

95. आयातों में हुई वृद्धि आवेदकों की बिक्री में हुई वृद्धि की तुलना में कम है।

96. आवेदक पुनर्गठन योजना का सार्थक सारांश प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

#### दि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के विचार

97. पिछले कुछेक वर्ष के दौरान कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड की आयात कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।

98. अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू विनिर्माताओं ने भी कीमतों में वृद्धि की है।

99. इस उद्योग की अपार लाभप्रदता के आधार पर ही बीआईएलटी ने वर्ष 2009 के अंत में क्षता बढ़ाकर 190000 टन कर ली है और जे एण्ड के पेपर लि. ने वर्ष 2007-08 के मध्य में 60000 टन प्रति वर्ष क्षमता का वर्धन किया है।

100. कच्चे माल की कीमतों में तेजी से हुई गिरावट को देखते हुए घरेलू विनिर्माताओं ने कागज और पेपर बोर्ड की कीमत घटाने के बजाय रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के माध्यम से राहत की माँग की है।

101 डी जी सी आई एस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कागज और पेपर बोर्ड के आयातों में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है। बल्कि आयातों में तेजी से गिरावट आई है

102 भारत में अभी भी मुद्रित सामग्री के निर्यात हेतु अपेक्षित कागज की किस्मों का विनिर्माण नहीं किया जाता।

103 वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान घरेलू उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

104 क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई है।

105 आवेदकों के वार्षिक तथा त्रैमासिक परिणाम दर्शाते हैं कि लाभप्रदता अत्यंत संतोषजनक है और किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है।

106. कागज जन उपयोग और उपभोग की एक अनिवार्य वस्तु है। कीमतों में कोई भी संशोधन करने पर सरकार का साक्षरता के प्रसार का कार्यक्रम प्रभावित होगा।

#### **थॉमसन प्रेस (इंडिया) लि. के विचार**

थॉमसन प्रेस (इंडिया) लि. ने अपने काउंसिल के जरिए निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं :-

107 आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन में विचाराधीन उत्पाद की समुचित परिभाषा नहीं दी गई है।

108 आवेदन में दिए आयात संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि इसमें कतिपय जी एस एम किस्म का कोटेड पेपर शामिल है जिसका विनिर्माण भारत में नहीं किया जाता।

109. आवेदन में चीन, इंडोनेशिया आदि में मांग में गिरावट, सुदूर पूर्व में भारी क्षमताओं के सृजन, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूरोप में भारी मात्रा में मालसूचियां इकट्ठा हो जाने, कम कीमत पर अंधाधुंध आयातों के संबंध में अप्रमाणित दावे किए गए हैं।



110. आवेदन में गोपनीयता का अत्यधिक दावा किया गया है ।
111. यह मामला साक्ष्यों की सत्यता एवं पर्याप्तता की जांच किए बिना शुरू किया गया है ।
112. वित्तीय परिणामों अथवा सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर कोई क्षति अथवा क्षति का खतरा नहीं है ।
113. कारणात्क संबंध को सिद्ध नहीं किया गया है ।
114. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध है क्योंकि इसकी परिणति भारतीय प्रकाशन उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि में होगी ।
115. आवेदकों को यह सिद्ध करना चाहिए कि यदि शुल्क नहीं लगाया जाता है तो भारत में कामज उद्योग किस प्रकार प्रभावित होगा ।
116. उच्च ऊर्जा लागत क्षति का एक कारक हो सकता है परन्तु इससे आयातों में वृद्धि सिद्ध नहीं की जा सकती ।

#### अन्य पक्षकारों के विचार

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों का सारांश निम्नानुसार है:-

117. आवेदन में आयातों, उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, मालसूचियों तथा लाभ से संबंधित आंकड़ों के संबंध में सही तथा पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ एवं घाटे तथा अन्य कारकों के बारे में दी गई सूचना गंभीर क्षति की द्योतक नहीं है ।
118. भारत में निगमित वानिकी की समस्या का समाधान रक्षोपाय उपायों के माध्यम से नहीं किया जा सकता ।
119. रक्षोपाय उपाय लागू करने की परिणति घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार पद्धतियों में होगी जिसके कारण स्थानीय मुद्रकों एवं प्रकाशकों तथा पैकरों को कभी और क्रीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा ।

120. घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, आयातों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है, बल्कि अन्य कारणों की वजह से हुई है, जिनके कारण रक्षोपाय शुल्क उपाय लागू नहीं किए जा सकते।

#### महानिदेशक के जाँच परिणाम

121. मैंने मामले के रिकॉर्ड तथा घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों एवं निर्यातक सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तरों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत निवेदनों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों का विवेचन नीचे दिए गए जाँच परिणाम में यथास्थान किया गया है।

122. **विचाराधीन उत्पाद:** आवेदकों ने आरोप लगाया है कि भारत में कोटेड पेपर तथा कॉपी पेपर के संवर्धित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है। घरेलू उद्योग मुख्यतः अध्याय शीर्ष 4810 के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आने वाले विशुद्ध रासायनिक लुग्दी से अनुरोध किया है कि उनके उत्पाद एच एस एन तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्ष 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200 एवं 48109900 के अंतर्गत आने वाले आयातित उत्पाद के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। आवेदकों ने आरोप लगाया है कि भारत में विशुद्ध रासायनिक लुग्दी से मुख्यतः निर्मित कोटेड पेपर और जो 8-अंकीय स्तर पर उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत आता है, के संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है।

123. पेपरों तथा पेपर बोर्डों का निर्माण रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया अथवा इन दोनों के संयोजन से प्राप्त लुग्दी से किया जाता है। इसके अलावा, लुग्दी नए पौध स्रोतों अथवा पुनर्चक्रित पेपर्स के उपयोग से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान आवेदन में रासायनिक प्रक्रिया के उपयोग से विशुद्ध रासायनिक लुग्दी से मुख्यतः निर्मित कोटेड पेपर शामिल है। कोटिंग एक तरफ या दोनों तरफ की जा सकती है। इन कागजों और पेपर बोर्डों की कोटिंग में आम तौर पर ब्लेड कोटिंग प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है।

घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त आठ अंकीय स्तर शीर्ष के अंतर्गत आने वाले उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, रासायनिक संरचना और अन्य मूलभूत विशेषताओं के रूप में एक समान हैं। इसलिए ये उत्पाद समान हैं तथा उत्पादों से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। गुणवत्ता के संबंध में संभावित छिटपुट अंतरों के बावजूद इन उत्पादों में समान

मूलभूत भौतिक विशेषताएं हैं और इनके समान अंतिम उपयोग हैं । इस प्रकार घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त के मद्देनजर रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त उत्पादों वाले उत्पाद क्षेत्र पर 'विचाराधीन उत्पाद' के रूप में विचार किए जाने की जरूरत है ।

124. कुछ हितबद्ध पक्षों का कहना है कि कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड भिन्न उत्पाद हैं और इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से सीधे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं । इसके अलावा गुणवत्ता के रूप में पेपर की गुणवत्ता भिन्न है, इस प्रकार इन सभी उत्पादों को एक साथ रखकर विचार करना उचित नहीं होगा ।

125. इस मामले का विश्लेषण किया गया । घरेलू उद्योग कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड का विनिर्माण करता है । कोटेड पेपर और पेपर बोर्ड का दोनों के आयात हुए हैं । इसके अतिरिक्त कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड का आयात विभिन्न आकारों में होता है और इन उत्पादों का घरेलू उद्योग द्वारा भी विनिर्माण किया जाता है । हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए उत्पादन के कोई साक्ष्य नहीं है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई विशेष वस्तु का भारत में आयात हुआ है लेकिन इसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया गया है और आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है ।

126. विचाराधीन उत्पाद एक उत्पादों का समूह है । क्या उत्पादों का समूह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद समूह के समान है या सीधे प्रतिस्पर्धात्मक है या नहीं का निर्धारण करने में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उत्पाद समूह सभी दूसरे उत्पाद समूहों के समान है या सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धी है । इसके विपरीत यह देखा जाना चाहिए कि क्या आयातित उत्पादों के प्रत्येक उत्पाद समान या सीधे प्रतिस्पर्धा रखते हैं ।

127. यह पाया गया है कि समूह में समान प्रकृति तथा समान मूलता वाले बड़ी संख्या में उत्पाद शामिल हैं । आठ अंकीय स्तर शीर्ष के अंतर्गत आने वाले आयातित उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, रासायनिक संरचना और अन्य मूलभूत विशेषताओं के रूप में एक समान हैं । इन उत्पादों का समान उपयोग होता है । ये आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ऐसे उत्पादों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अथवा प्रतिस्पर्धात्मकता की संभावना है । गुणवत्ता के संबंध में संभावित छिटपुट अंतरों के बावजूद इन उत्पादों में समान मूलभूत भौतिक विशेषताएं हैं और इनके समान अंतिम उपयोग हैं । इनकी बिक्री समान अथवा एकल बिक्री चैनल से किया जाता है । उपर्युक्त के मद्देनजर रक्षोपाय जांच के प्रयोजनार्थ कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड (उपर्युक्त यथावर्णित) 'जांचाधीन उत्पाद' हैं ।

128. घरेलू उद्योग: यह आवेदन (1) आई टी सी लिमिटेड पेपर बोर्ड एण्ड स्पेशियलिटी पेपर्स डिविजन, 106, सरदार पटेल रोड, सिकन्दराबाद-500003, आंध्र प्रदेश (2) वल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फस्ट इंडिया प्लेस, टावर सी, महारौली, गुडगांव रोड, गुडगांव (हरियाणा) - 122001 और (3) जे के पेपर लिमिटेड, नेहरू हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा दायर किया गया है। जिसका समर्थन आयातों पर सुस्त्रोपाय शुल्क लगाने के लिए इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, पीएच डी हाउस (चौथी मंजिल) 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया (खेल गांव के सामने) नई दिल्ली-110016 द्वारा किया गया है। यह तीनों आवेदक वर्जिन कैमिकल पल्प को छोड़कर कोटेड पेपर तथा पेपर बोर्ड का 100 प्रतिशत के लगभग उत्पादन करते हैं। इसलिए ये उद्योग सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

129. जांच अवधि - घरेलू उद्योग ने वर्ष 2008-09 (दिसम्बर तक) के लिए सूचना प्रस्तुत की है और वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के बीते 2 वर्षों की सूचना के साथ 2008-09 (दिसम्बर तक) की तुलना के आधार पर गंभीर क्षति का दावा किया है। प्रारंभिक निष्कर्ष वर्ष 2008-09 (दिसम्बर तक) जांच अवधि पर आधारित थे। घरेलू उद्योग ने इसके बाद के समय के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह कहते हुए कि जांच अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उन्होंने तर्क दिया है कि बाद की सूचना देना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह सुस्त्रोपाय जांच को शुरू करने से प्रभावित हो सकती है।

130. इस मामले की जांच की गई। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 सीमाशुल्क टैरिफ (सुस्त्रोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियमावली 1997 गैट के संगत अनुच्छेद XIX अथवा सुस्त्रोपाय पर करार विशेष रूप से यह परिभाषित नहीं करते हैं कि जांच अवधि क्या होनी चाहिए। तथापि, जांच अवधि के मुद्दे पर अर्जेण्टीना फुटवियर पर बने पैनल की रिपोर्ट के साथ-साथ अर्जेण्टीना फुटवियर पर अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार किया गया, जिसे नीचे दिया जा रहा है।

### “ अर्जेंटीना-फुटबल के आयातों पर रक्षोपाय : पैनल की रिपोर्ट ”

8.216 जहाँ तक जाँच में घरेलू उद्योग की स्थिति में परिवर्तन के विश्लेषण में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की गई तुलनाओं पर लगभग पूर्ण भरोसा किए जाने का संबंध है, हमारी भी वही चिंता है जैसी कि “ संवर्धित आयातों ” के विश्लेषण के बारे में ऊपर नोट किया गया है । यहाँ हम इस बात को खासतौर पर नोट करते हैं कि यदि मध्यवर्ती रूझानों पर क्रमबद्ध ढंग से विचार नहीं किया जाता है और उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी “ समस्त संगत कारकों ” का विश्लेषण करने के बारे में अनुच्छेद 4.2(क) की अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णरूप से आकलन नहीं होता है । उदाहरणार्थ, ऐसी किसी उद्योग की स्थिति, जिसका उत्पादन एक वर्ष में काफी कम हो जाता है परंतु उसके बाद उसमें लगातार सुधार होता है यद्यपि कुछ स्तर तक यह शुरुआती स्तर से कुछ कम रहता है तो यह स्थिति तर्कसम्मत ढंग से ऐसे किसी उद्योग की स्थिति से अलग होगी जिसके उत्पादन में विस्तारित अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है । एक छोर से दूसरे छोर तक का विश्लेषण दोनों मामलों में एक समान होना चाहिए जबकि वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों एवं रूझानों पर विचार करने से पूर्णतः विपरीत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ।

हमारा मानना है कि विभिन्न क्षतिकारकों में जांच अवधि के दौरान परिवर्तनों पर विचार करना इस बात के निर्धारण हेतु अनिवार्य है कि क्या किसी उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का आसन्नवर्ती खतरा उत्पन्न हो गया है । मध्यवर्ती रूझानों पर विचार किए बिना एक छोर से दूसरे छोर तक की तुलना से अपेक्षानुसार समस्त संगत कारकों का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान करने की संभावना नहीं है ।

### अपीलीय निकाय की रिपोर्ट

नोट 130.

पैनल ने पैनल रिपोर्ट के पैरा 8.166 की पाद टिप्पणी 530 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान काल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें यह उल्लेख है कि “ यह प्रतीत होगा कि जांच अवधि का शुरुआती बिंदु कोई भी हो उसे हाल की निकटतम अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए ” (जोर दिया गया) । यहाँ हम पैनल से सहमत नहीं हैं । हमारा मानना है कि संगत जांच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए अपितु उसे हाल की अवधि होनी चाहिए ।

131. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो रक्षोपाय करार और न ही डब्ल्यूटीओ के संगत प्रावधानों में जांच अवधि की विशिष्ट परिभाषा या व्याख्या निहित नहीं है । अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह जाँच परिणाम दिया गया है

कि संगत जाँच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए; जाँच अवधि हाल की अवधि होनी चाहिए। अतः आवेदन दायर करने के बाद की अवधि की रक्षोपाय जांच में अनदेखी नहीं की जा सकती। तथापि, प्राकृतिक न्याय की जरूरत को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जांच की शुरुआत के बाद प्राप्त या संगृहीत सूचना हितबद्ध पक्षकारों के पास उपलब्ध हो। जहां तक घरेलू उद्योग के तर्कों का संबंध है बाद की अवधि से संभावित सूचना की जांच करना आवश्यक नहीं है। यह नोट किया जाता है कि तथ्यों पर ध्यान दिए बिना या जांच शुरू करने के बाद की अवधि के लिए सूचना की जांच आवश्यक है या नहीं, इस प्रकार की कुछ सूचना के घरेलू उद्योग के नवीनतम स्थिति का पता करने में सहायक होगी।

132. तथापि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने आवेदन में संदर्भित सूचना से इतर अवधि की सूचना पर विश्वास किया है। इस प्रकार जांच अवधि वर्ष 2008-09 (दिसम्बर तक) की अवधि के लिए सीमित है।

133. आयातों में वृद्धि: निम्नलिखित सारिणी में जांचाधीन उत्पाद के आयात दिए गए हैं। औसत मासिक आयात वर्ष 2007-08 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2009 के दौरान बढ़कर 52.59 % हो गए। औसत मासिक आयात वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में 124 % तक बढ़ गए। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि आयातों में वर्ष 2008-07 से बढ़ोतरी हो रही है।

	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसम्बर तक)
कुल आयात (मी टन)	106993	132684	151848
औसत मासिक आयात (मी टन)	8916	11057	16872

134. आयातों का मूल्य: जांचाधीन उत्पाद की आयात कीमत 2006-07 में 655 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 763 अम.डा. प्र.मी.टन और वर्ष 2008-09 में 910 अम.डा. प्र.मी.टन तक बढ़ोतरी हो गई। आयात कीमतों में वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में क्रमशः 16.5% और 19.3% हो गई। इस प्रकार यह देखा गया है कि आयात कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसम्बर तक)
मूल (अम.डा./मी.टन)	655	763	910

135. उत्पादन की तुलना में आयातों का हिस्सा : निम्नलिखित तालिका में उत्पादन की तुलना में आयातों का ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 2007-08 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 08 के दौरान आयातों के हिस्से में 6% की वृद्धि हुई है।

तालिका 3

	2006-07	2007-08	2008-09 ( दिसंबर तक )
आयातों का हिस्सा (%)	30%	33%	39%

136. अतः यह नोट किया जाता है कि आयातों में मात्रात्मक रूप में और तुलनात्मक रूप में वृद्धि हुई है। तथापि, आयात पूर्ववर्ती वर्ष से अधिक कीमत पर हुए हैं।

### गंभीर क्षति और उसके कारण

#### सांविधिक संरचना :

137. “ गंभीर क्षति ” से ऐसी क्षति अभिप्रेत है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति आई हो;<sup>1</sup>

138. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2(क) और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण का आकलन करने के लिए कुछेक सूचीबद्ध कारकों और संगत कारकों का मूल्यांकन अपेक्षित होता है। तथापि, ये उपबंध उस मूल्यांकन के लिए उचित नहीं ठहरते हैं कि ऐसे मूल्यांकन से किस बात का पता चलेगा। ऐसा मूल्यांकन अलग-अलग मामलों में उस मामले विशेष के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति के आधार पर अलग-अलग उद्योग के लिए अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन से अनिवार्यतः यह पता नहीं चलेगा कि प्रत्येक कारक में “ गिरावट ” आ रही है। उदाहरणार्थ एक मामले में बिक्री में पर्याप्त गिरावट आ सकती है, रोजगार और उत्पादकता से घरेलू उद्योग की स्थिति में “ अत्यधिक समग्र विकृति ” का पता चल सकता है। दूसरे मामले में कुछेक कारक में गिरावट नहीं आ सकती है परंतु समग्र स्थिति से उद्योग की “ अत्यधिक समग्र विकृति ” का पता चल सकता है। इस प्रकार, समग्र सूचीबद्ध कारकों एवं अन्य किसी

<sup>1</sup> सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(ग)

संगत कारक की तकनीकी जांच के अलावा यह आवश्यक है कि उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों के मद्देनजर घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।<sup>2</sup>

139. तदनुसार, गंभीर क्षति के उन समस्त कारकों, जिनका उल्लेख नियमों में है तथा ऐसे अन्य कारकों, जो संगत हैं, का विश्लेषण करने में उन पर विचार किया गया है। किसी भी कारक को निरर्थक नहीं माना गया है। घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए संगत व्यापार चक्र एवं प्रतिस्पर्धा की स्थितियों, जो प्रभावित उद्योग के लिए संगत हैं, पर विचार किया गया है।

### कारकों की जांच

140. आयातों की वृद्धि दर : आयातों की वृद्धि दर 2007-08 में 24.01% से बढ़कर 2008-09 में 52.59% हो गयी है।

तालिका 4

	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसंबर तक)
आयातों की वृद्धि दर		24.01%	52.59%

141. आयातों द्वारा कब्जा किए गए घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा : जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में 6% की वृद्धि हुई है। बाजार हिस्से में 2006-07 की तुलना में 2007-08 में 3% की गिरावट आई है।

तालिका 5

	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसंबर तक)
घरेलू उद्योग का हिस्सा (%)	70	67	61

142. उत्पादन : वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत मासिक उत्पादन में 18.81% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में उत्पादन में 8.14% की वृद्धि हुई है।

<sup>2</sup> डब्ल्यूटीओ की अर्जेंटीना फुटबियर मामले की अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 के आधार पर



## तालिका 6

	2006-07	2007-08	2008-09 ( दिसंबर तक )
कुल उत्पादन (मी. टन)	246664	266751	237699
औसत मासिक उत्पादन (मी. टन)	20555	22229	26411

143. बिक्री : वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत मासिक बिक्री में 18.81% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में बिक्री में 8.14% की वृद्धि हुई है।

## तालिका 7

	2006-07	2007-08	2008-09 ( दिसंबर तक )
कुल बिक्री (मी. टन)	252146	264452	236565
औसत मासिक बिक्री (मी. टन)	21012	22038	26285

144. क्षमता उपयोग : घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वर्ष 2007-08 और 2008-09 (दिसंबर तक) के दौरान 2500 मी. टन/माह की वृद्धि हुई। स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2008-09 (दिसंबर तक) में स्थापित क्षमता वर्ष 2007-08 में 67% से बढ़कर 74% हो गयी। इसका तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग उस मात्रा तक उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ था जो क्षमता विस्तार से अधिक है।

## तालिका 8

	2006-07	2007-08	2008-09 ( दिसंबर तक )
कुल स्थापित क्षमता (मी. टन)	366000	396000	319500
स्थापित क्षमता (मी. टन/माह)	30500	33000	35500
क्षमता उपयोग	67	67	74

145. रोजगार एवं उत्पादकता : घरेलू उद्योग ने अपने रोजगार और उत्पादकता के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है और इस प्रकार कोई विश्लेषण नहीं किया जा सका।

146. लाभप्रदता : लाभप्रदता में वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में 2808.98 की वृद्धि हुई और आरओसीई प्रतिशत वर्ष 2006-07 में 14.06% से घटकर वर्ष 2007-08 में 7.34% हो गया और पुनः 2008-09 (अप्रैल-दिसंबर, 08) में घटकर 4.27% हो गया। लाभप्रदता में यह गिरावट मुख्यतः कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत और मूल्य ह्रास के कारण आई है। घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि कच्ची

सामग्री की लागत नैगमिक कृषि के अभाव और भारत में ऊर्जा की अधिक लागत के कारण अधिक रही है। वर्तमान मामले में मूल्य ह्रास क्षमता विस्तार हेतु संबद्ध वस्तु में संवर्धित निवेश के कारण अधिक हुआ है। ये कारण संवर्धित आयातों से संबंधित नहीं हैं। यह भी देखा गया है कि इस अवधि में आयात कीमत में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि संवर्धित आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव बन रहा है। अतः लाभप्रदता में गिरावट आयातों में वृद्धि का कारण नहीं है।

तालिका 9

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09 (दिसंबर तक)
पीबीटी प्रति मी. टन	4187.26	1378.28	317.69
आरओसीई % (ईबीआईटी/लगाई गई पूंजी)	14.06	7.34	4.27

147. उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन : घरेलू उद्योग ने वर्ष 2007-08 और 2008-09 (दिसंबर तक) में स्थापित क्षमता का विस्तार किया है। इस अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 2007-08 में केवल 8.14% की वृद्धि की तुलना में 2008-09 (दिसंबर तक) के दौरान उत्पादन और बिक्री में 18.81% की वृद्धि हुई है। स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग में 7% की वृद्धि हुई जो 2007-08 में 67% से बढ़कर 2008-09 में 74% हो गया। वर्ष 2008-09 (दिसंबर तक) के दौरान उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग अधिकतम बना रहा। लाभप्रदता में कुछ गिरावट आई परंतु घरेलू उद्योग मंदी की अवधि में भी लाभ में बना हुआ है। इसके अलावा लाभप्रदता में गिरावट के विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह गिरावट संवर्धित आयातों के कारण नहीं आई है।

148. “गंभीर क्षति” पद से घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति अभिप्रेत है। लाभ कमाने वाले घरेलू उद्योग जिसका अधिकतम उत्पादन, अधिकतम बिक्री, अधिकतम क्षमता उपयोग रहा है और जिसने विचाराधीन समूची अवधि के दौरान क्षमता विस्तार किया है, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी स्थिति में पर्याप्त समग्र विकृति आई है। इसके अलावा, इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं है कि उच्चतर कीमतों पर हुए संवर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का खतरा बना हुआ है।

149. अतः घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने या गंभीर क्षति होने का कोई खतरा नहीं है।

150. चूंकि गंभीर क्षति होने या गंभीर क्षति होने का कोई खतरा नहीं है इसलिए संवर्धित आयातों के साथ उसके कारणात्मक संबंध का प्रश्न नहीं उठता।

**निष्कर्ष एवं सिफारिश**

151. उपर्युक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है या गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ है।

152. तदनुसार, कोटेड पेपर एवं पेपर बोर्ड के आयातों पर किसी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है।

[फा. सं. डी-22011/25/2009]

प्रवीण महाजन, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND  
CENTRAL EXCISE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2009

**Subject : Safeguard Duty investigation against imports of Coated Paper and Paper Board in to India-Final Findings**

**G.S.R. 824(E).—** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof;

**PROCEDURE**

1. An application was filed before me Under Rules 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by (1) ITC Limited -Paperboards and Specialty Papers Division, 106, Sardar Patel Road, Secunderabad – 500003, Andhra Pradesh, (2) Ballarpur Industries Limited, First India Place, Tower C, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon (Haryana) – 122001 and (3) JK Paper Limited, Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 supported by Indian Paper Manufacturers Association, PHD House, (4th floor), 4/2 Siri Institutional Area (Opp. Asian Games Village), New Delhi-110 016 for imposition of Safeguard Duty on increased imports of Coated Paper and Paper Board made primarily from virgin chemical pulp into India to protect the domestic producers of Coated Paper and Paper Board against serious injury and continued threat of serious injury caused by the increased imports of Coated Paper and Paper Board made primarily from virgin chemical pulp into India..
2. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Coated Paper and Paper Board into India was issued under Rule 6 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 20<sup>th</sup> April, 2009 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.
3. A copy of the notice was sent to the Governments of exporting countries through their Embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

**Domestic Producers**

- i. ITC Limited -Paperboards and Specialty Papers Division, Secunderabad, Andhra Pradesh.
- ii. Ballarpur Industries Limited, Gurgaon, Haryana.
- iii. JK Paper Limited, New Delhi.

**Domestic Producers Association**

- i. Indian Paper Manufacturers Association, PHD House, (4<sup>th</sup> floor), 4/2 Siri Institutional Area, (Opp. Asian Games Village), New Delhi-110 016

**Importers and Users**

- i. Chimanlal Fein Paper Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra.
- ii. Infinity Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra
- iii. Ajanta Offset and Packaging Limited, Faridabad, Haryana.
- iv. Aero Exports, Manesar, Gurgaon, Haryana.
- v. Nutech Photolithographic, New Delhi.
- vi. Replika Press Private Limited, Haryana.
- vii. Brijbasi Printers, New Delhi.
- viii. Rajaram, Chawri Bazar, Delhi.
- ix. Shoba Cards, Darya Ganj, New Delhi.
- x. Suneja Sons, Chawri Bazar, Delhi.

**Exporters & Foreign Producers**

- i. Gold East Paper(Jiangsu)Co.,Ltd., 8Xing Gang Dong RD., Dagang, ZhenJiang, JiangSu, China, 212132
- ii. APP – Indonesia, Pt. Pindo Deli Pulp and Paper Mills, Plaza B11- Menara II, 9th Floor, JL MH Thamrin no. 51, Jakarta.
- iii. SAPPI : M/s Sappi Deutschland, GMBH Berliner allee, 14 D- 30175 Hannover,C/o Sappi Singapore pte Anson Road 079903
- iv. Stora Enso Oyj, P.O. Box 309, FI-00101 Helsinki, Finland.
- v. Chemming Paper Co. Ltd, Nanchan Changbei Economic and Techniaci Development zone, Jiangxi, China
- vi. M/s. Stora Enso Suzhou Paper Co. Ltd 600 Binhe Road, Sozhou New District Suzhou City, China.
- vii. M-real corporation, PO Box 20, Metsa 02020, Finland
- viii. Moorim Paper Co., 281 – 1 Sangyong – dong , Jinju – sl , 660903, South Korea
- ix. Hong Wong Paper Mfg. Co. Ltd, #14,Imgwang Bldg , Migeun – dong , Seoul , South Korea
- x. Hansol Paper Co. Limited , 22nd floor , Hansol Bldg, 736-1 ,Yeoksam – dong Gangnam – gu –Seoul, 135 – 080 , South Korea.

- xi. Gold East Trading (HONGKONG) Co Ltd, Unit 501-504A, Empire Centre 68 Mody Road, T Simsha Tsui East Hongkong
- xii. Kowa Company Ltd, 6-29 Nishiki 3- Chome Naka-Ku Nagoya, Japan
- xiii. Vital Solutions pte Ltd, Singapore 069532
- xiv. Daiei Paper (S.A.) Pte Ltd, 3. Shenton way, # 11-08, Shenton House, Singapore
- xv. Cellmark asia Pte Ltd, 47 Scotts road, # 12-01 Goldbell Towers, Singapore

### **Exporting Nations**

- i. The Republic of China through their Embassy in New Delhi.
  - ii. Jakarta through their Embassy in New Delhi.
  - iii. Singapore through their Embassy in New Delhi.
  - iv. Japan through their Embassy in New Delhi.
  - v. Hongkong through their Embassy in New Delhi.
  - vi. Republic of Korea through their Embassy in New Delhi.
  - vii. Finland through their Embassy in New Delhi.
4. After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time were allowed and the parties concerned were accordingly informed.
5. After expeditious conduct of investigation, preliminary findings were issued on 24<sup>th</sup> April 2009. On the basis of the preliminary findings it was seen that increased imports of coated paper and paperboard have caused serious injury to domestic producers of coated paper and paperboard. The Director General (Safeguards) recommended safeguard duty at the rate of 20% (twenty percent) ad-valorem to be the minimum required safeguard duty to protect the interest of domestic industry and imposed on imports of "coated paper and paperboard made primarily from virgin chemical pulp and classified under sub-heading Nos. 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200 and 48109900 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975" into India.
6. A public hearing was held on 11<sup>th</sup> September 2009, notice for which was sent on 12<sup>th</sup> August, 2009. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.

7. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places without referring to specific name of the interested party for the sake of brevity.
8. The information presented by domestic producers was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. Further, the cost data has also been verified and certified by cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.

### **Views of Domestic Producers in India**

The applicants have made following submissions:-

9. The domestic industry has said that product falling under 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200 and 48109900 of HSN as well as Customs Tariff Act, 1975 should be considered as the 'product under consideration'.
10. Surge in imports are taking place at lower price, making them lose their market share.
11. Fall in demand in exporting countries has forced manufacturers in those countries to get rid of their surplus inventories through excessive discounts of export and this is a cause for sudden increase in imports which is causing serious injury and threatening to cause serious injury to domestic industry.
12. Profitability and return on capital employed of domestic industry has gone down.
13. Imposition of safeguard duty on Coated Paper and Paper Board shall not cause harm to public interest as prices of domestic Coated Paper and Paper Board are more or less stable in India.
14. As per Budget Speech of 2005-06 it has been the policy of Government of India to encourage capacity additions in paper industry so that India can reduce its dependence on imports.
15. The size of Indian Paper Industry is too small when compared to global size of the industry. A small diversion of paper from foreign producers is capable of killing the Indian paper industry.
16. Paper Industry is a labour intensive industry. The industry provides employment to more than 1.2 lakh people directly and 3.4 lakh people indirectly down the line i.e. 4.6 lakh people all together.
17. The coated paper and paperboard segment is supporting 48750 families i.e. roughly 2.5 lakh people through plantation activities.
18. The paper industry is highly capital intensive with a long gestation period. Ballarpur Industries Limited (BILT) has added 1, 90,000 MT additional capacity

and JK Paper Limited has added 60,000 MT additional capacities in last two years in the Coated Paper and Paperboards segment.

19. Globally, paper industry has realized a linkage between production of paper and the farming community thereby infusing huge capital in agricultural economy.
20. The paper industry is primarily rural based with close linkages with the farming community. Over the years it has evolved into an agro-based industry from its earlier character of a forest-based industry.
21. The coal which is the main fuel for generation of steam and power required for manufacturing paper is available at a cheaper price to foreign producers.
22. The capacities of overseas mills are huge and not comparable with Indian mills.
23. The paper industry is actively pursuing agro forestry in the vicinity of factories to generate employment opportunities in rural India.
24. Large agricultural subsidies being provided to farmers and agri-business corporations in the rich and developed countries. Protecting paper industry in a way, amounts to protecting the Indian farmers engaged in pulp wood plantation. Therefore the imposition of safeguard duty on coated paper and paper board is in the larger public interest.
25. In India roughly two third of the population depends on agriculture, the interest of farming community cannot be overlooked. Farmers' interest outweighs everybody else's interest worldwide.
26. The allegation of Printers Association that the products manufactured by domestic industry are of poor quality is baseless. It is to be submitted that coated paper and paper board manufactured by domestic industry is of world class quality and the same has been certified by Indian as well as international certifying agencies. All the units are holding ISO certifications.
27. In the recent period of first nine months of 2008-09 monthly imports of subject goods have increased from 11057 MT per month in 2007-08 to 16872 MT per month; a growth of more than 50% from 2007-08. The imports of coated paper and paperboard have thus increased in absolute terms as well as in relative terms compared to total domestic market.
28. The Export price to India has shown a steep decline during the period of investigation since September 2008, the period in which situation became worse.
29. When the import prices started crashing, some manufacturers of Indian domestic industry finding it difficult to compete with imported product closed their plants.
30. The Profitability and return on capital employed of domestic industry has gone down. The plants have seen drastic reduction in profitability and Return on capital employed.
31. The leading information provider for the Global Forest Products Industry RISI in its Outlook Briefings 2009 has reported following unforeseen developments relevant for the coated paper and paperboard segment of paper industry viz. fall in Demand in developed countries, price trends of imports of Coated Paper, demand growth for paper and board is expected to be more muted than in the early part of this decade.

32. The Chinese Central Government is running a national plan of building a complete industrial chain between the forestation and paper industry by 2010. As a result massive capacities additions have been announced in China.
33. Unprecedented uneven recession in various countries has led to sudden increase of imports into India, which has a better growth compared to other countries.
34. Adjustment Plan: The present capacities of 6.14 lakh MT can take care of present domestic demand of around 4.5 lakh MTs. Further capacity expansions are planned to take care of future growth in the demand of coated paper and paperboard. We have already submitted a detailed concrete and viable adjustment plan (confidential) which focuses on Capacity expansion, cutting raw material costs through aggressive agro forestry measures, Cutting energy costs, Cutting other costs. We have already demonstrated by our capacity expansion of 2008-09 that we are committed towards this adjustment plan.

### **VIEWS OF EXPORTERS**

35. Exporters M/s. Asia Pulp and Paper Co. Ltd. , M/s Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., M/s PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Indonesia, M/s PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, Indonesia, M/s Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd., M/s Gold East Trading Co. Ltd. (China), M/s Ningbo Zhonghua Paper Co. Ltd. have submitted the following points for consideration through their counsel.
36. The adverse conditions prevailing in India as stated by the domestic industry are irrelevant from the point of view of Safeguard Duty Investigation. None of these factors are the cause of the alleged increase in imports.
37. In the submissions of the Domestic Industry they are attributing their so called injury to other factors and not to the alleged increased imports. Injury caused to the domestic industry by factors other than increased imports 'shall not be attributed to increased imports.'
38. That the Domestic Industry changes the period of investigation as per their whims and fancies. The domestic industry has chosen the last three quarters for inventory growth analysis. The period of investigation is not compared against the previous periods as has been done for certain other parameters
39. The Applicants have failed to provide the correct computation of total demand in the country.
40. The imports in the month of April, September, October, December 2008 show a decreasing trend.
41. The contention of the applicants regarding the falling import prices is totally false and incomplete. No information has been supplied for the previous years on this.
42. There is no decrease in Sales and Market Share of the Domestic Industry. As already submitted in the written submissions, it is evident that there is no loss of market share.
43. Demand analysis has to be done in the context of the total domestic sales and not only for the applicant domestic industry.



44. The Domestic Industry despite the “growing market” was not “equipped” to handle the needs of the market which was fulfilled by the imports of the necessary goods in the country.
45. The statements with regard to restructuring and unforeseen circumstances made by the applicants are nothing but conjectures and surmises.

### **Views of Confederation of European Paper Industries (CEPI)**

The CEPI represents the European Paper industry based in Europe, which accounts for about 95 % of the total European paper capacities. CEPI have submitted the following comments on the case:

46. Although there is some increase in imports, the figures reported by the Indian authorities is not correct. The share of paper & board coming from Europe into India has decreased over the last year. The share which was 45 % in 2000 went down to 34 % in 2007. According to the EU statistics, the exports of the paper grades targeted by the Indian authorities to India have decreased by 5 % in 2008 compared to 2007 and have shown a decrease of close to 30 % over the first 5 months of 2009.
47. The injury analysis is incomplete. Analysis should have been carried out on the basis of trends established for full years during the investigating period. The injury analysis for 2008-09 was based on a period of only 9 months for that year.
48. Production and sales figures given in the complaint shows an overall increase and profit is still close to 5 % which does not point to serious injury.
49. The actual causes of any serious injury (if any) are not clearly identified. The causality analysis is also not conclusive.
50. Indian domestic paper and board industry are not able to meet the needs of the Indian population.
51. The analysis on the public interest test is poor as substitutability of products locally produced and those imported cannot be limited to the price.
52. The adoption of safeguard measures would lead to monopolistic practices by the domestic industry leading to shortages and much higher prices for the local printers and publishers and packers.

### **Views of the European Commission**

53. The injury analysis is neither complete nor objective or conclusive and lacks transparency. The aggregated figures relating to the relevant injury indicators have not been disclosed. The comparability of data to analyze trends was not ensured. The period analysed covered the fiscal years 2006-07, 2007-08 and only 9 months of 2008-09.
54. Production and sales increased overall, and profit is still close to 5 %, which does not point to serious injury.

413448/09-5

55. The causal link analysis between the imports and the alleged serious injury is weak and incomplete.

**Views of M Real Corporation, Finland:**

M Real Corporation, Finland has submitted the following views through their counsel.

56. The data regarding imports are totally wrong. More than one like product has been considered as PUC leading to wrong analysis. Assuming the applicant's data to be correct, it reflects that the share of imports in the domestic market has increased by less than 3 % per year which is not significant. Also during the corresponding period, sales of domestic producers have grown by 19 % over the last year. There is as such no surge in imports.
57. M Real products are totally different in quality and price as compared to the domestic paperboard. The product exported by M Real to India does not compete with the product manufactured by the applicants and what ever demand is there for the product exported by M Real has to be met through imports, as no product is produced by the domestic industry is able to meet the characteristics and specifications of M Real's product. No injury is caused by these products let alone serious injury.
58. Applicants have attributed the increase in imports to the global recession which is not an unforeseen circumstance. Recession finds mention in applicants' Annual Reports. Now as announced by our government, turnaround has started and all economic parameters are showing reversal of recessionary trend- so any impact of recession on the domestic industry is no longer there.
59. Applicants do not form the domestic industry as their collective output constitutes less than 50 % of the total production. As per ITC Annual Report 2007-08, top 5 manufacturers account for only 45 % of the total domestic production of PUC and there are over 100 manufacturers. For Coated Paper and Paper Board, even if taken together, the 3 applicants even as per their own submission show production of only 314970 MT but total domestic production is 1.24 million MT.
60. Coated paper and paperboard are not like products and cannot be clubbed together.

**Views of Stora Enso Oyj, EU.**

Stora Enso Oyj, EU has submitted the following views through their counsel.

61. Lack of transparency and absence of accurate or adequate information in the application.
62. Applicants have presented fresh evidence at the Hearing that cannot be relied upon.
63. Stora Enso's coated paper products are unlike articles and do not substitute the domestic products.
64. No surge in imports noticed. Injury, if any, has not been caused by imports
65. Imports of coated paper are not coming at a low price.

66. From the market share, production, inventories, capacity and profits data provided by the applicants' it appears there is no 'serious injury' caused.
67. The Indian customers will suffer and costs of educational publications are likely to rise if safeguard measures are imposed.
68. Export trends in coated paper market, both globally and within India are not 'unforeseen developments'.
69. No re-structuring or adjustment plan was made in the application.
70. The real problem of corporate forestry in India cannot be resolved through safeguard measures.

### **VIEWS OF IMPORTERS**

#### **Views of the Chemicals & Allied Products Export Promotion Council**

71. The cost of basic raw materials i.e. pulp and fuel have gone down and international paper manufacturers have passed the benefits to the consumers. Indian printers printing for the international market have to give competitive rates at international quality. Once safeguard measures are imposed, the Indian printers will lose the competitive edge.
72. The exporters are not selling their product below cost. Since the cost of raw material fell so did the price of the final product. The exporters are all making profit.
73. The share of imported paper is just 1.13 % of the total domestic consumption.
74. The Indian paper manufacturers are making profit as per their annual returns. Also they have no inventory at the end of the month.
75. Imported paper is needed by Indian printers because of its quality, availability on time and some varieties are not manufactured in India.
76. If safeguard duty is imposed on paper, prices of paper will increase by 20-25 %. It will make books more expensive. Libraries, readers, authors will suffer. Education will become more expensive.
77. Indian printers will become non-competitive in the international market. India will lose the advantage of being a printing hub for the international publishing industry.
78. Safeguard measures will help select paper manufacturers of India at the cost of printing and publishing industry.

#### **Views of Federation of Paper Traders Association:**

Federation of Paper Traders Association has submitted the following views through their counsel.

79. The applicants do not have the standing to file the application as they constitute only 38 % of the domestic industry. The application has been filed by ITC Limited, Ballarpur Industries Limited and J.K. Paper Limited on behalf of domestic producers and supported by IPMA. But the application provides data for only the three producers who constitute 38 % of the total domestic production.

80. Data is provided in the application for only three producers accounting for 38 % of the production and not for all members of IPMA.
81. The application does not provide critical data available in the public domain under guise of confidentiality without providing valid reasons for keeping it confidential as provided under Rule 7(2).
82. The application does not provide the adjustment plan which is in violation of the rules.
83. Coated Paper and Paperboard are distinct products, not sharing the manufacturing process and are not easily substitutable in their end uses. These cannot be treated as like and directly competitive products.
84. The application fails to prove serious injury or threat of serious injury as the application does not provide data / information showing any unforeseen circumstances, surge in imports, fall in sales or market share, fall in international prices due to reduction in raw material prices, fall in capacity utilization, loss of employment or loss in annual reports.
85. The application fails to prove any causal link, a reasoned explanation for quantum of duty.
86. The injury caused to the applicants is not because of increased imports but can be attributed to other factors.
87. The applicants have not provided the data regarding the number of people employed by the paper industry.
88. The imposition of safeguard duty will affect the members of the Federation and the businesses that buy paper from the Federation.
89. The agro forest industry does not manufacture the product but it is merely an input used in the manufacture of the product. The plight of the farmers involved in the agro forestry is important to the nation as a whole. This investigation centers around the paper industry. Safeguard investigations are product specific, i.e. they are on like or directly competitive products.
90. The applicants have not provided any breakup as to how much investment out of Rs 13,000/- crores is channeled to other products.
91. The raw material scenario in India is not relevant to the current investigation. The Government of India has made a policy decision not allowing corporate farming in India, while Governments around the world have allowed the same. Therefore the right solution is to approach the government to change its policy rather than imposition of safeguard duty.
92. Energy costs are independent of the quantity of imports. So the injury caused by high energy costs cannot be attributed to increased imports.
93. The applicant's claim that all the products under Chapter 48 have similar use is misleading.
94. Data provided by a supporter of the application, IPMA, clearly shows that the applicants account for a mere 38 % of the domestic production.
95. Increase in imports has been less than the increase of sales of the applicants.
96. The applicants have failed to provide a meaningful summary of restructuring plan.

**Views of the All India Federation of Master Printers**

97. The import prices of coated paper and paperboard have shown a sharp increase during the last few years.
98. Alongwith the international market, the domestic manufacturers also increased the prices.
99. Based on the enormous profitability of the industry, BILT increased capacity by 190000 T by end 2009 and J K Paper Ltd. added 60000 T per annum capacity in mid 2007-08
100. Rather than lowering the price of paper and paperboard in view of the sharp decline in raw material prices, the domestic manufacturers have sought for relief by getting safeguard duty imposed.
101. There has been no surge in imports of paper and paperboard as per figures obtained from DGCIS. Rather there is a sharp decline in imports.
102. India still does not manufacture varieties of papers required for export of printed materials.
103. There is a significant increase in domestic production and sales during 2008-09 over 2007-08.
104. There is no fall in capacity utilization.
105. The annual and quarterly results of the applicants show that profitability has been more than satisfactory and there is no injury whatsoever.
106. Paper is an essential commodity of mass utility and consumption. Any revision in prices will affect the Government's programme of spreading literacy.

**Views of Thomson Press (India) Ltd.**

Thomson Press (India) Ltd. has submitted their views through their counsel

107. The application filed by the applicants does not contain a proper definition of the product under consideration.
108. Import data provided in the application is not reliable as it includes certain gsm-types of coated paper that were not manufactured in India.
109. Application contains unsubstantiated claims concerning fall in demand in China, Indonesia etc., huge capacities created in Far East, huge inventory piled up in China, Indonesia, Thailand, Europe, indiscriminately low priced imports.
110. Excessive claims of confidentiality in the application
111. Case initiated without examination of the accuracy and adequacy of the evidence.
112. No injury or threat of injury based on financial results and public data.
113. No causal link established.
114. Imposition of safeguard duty is against public interest as it shall result in further increase in the cost of production for the Indian publishing industry.
115. Applicants must establish how the paper industry in India will be affected if duties are not imposed.
116. The high energy costs can be a factor to injury but it cannot prove increase in imports.

**Views of others:**

The summary of views presented by other interested parties is as follows:

117. Accurate or adequate information regarding imports, production, sales, market share, inventories, and profit data are not provided in the application. The information submitted by the applicant relating to sales, production, capacity utilization, profit and losses and others do not show serious injury.
118. The problem of corporate forestry in India cannot be resolved through safeguard measures.
119. Introduction of safeguard measures would lead to monopolistic practices by the domestic industry leading to shortages and much higher prices for the local printers and publishers and packers.
120. Injury to the domestic industry, if any, is not due to increase in imports but other reasons for which safeguard measures cannot be introduced.

**Findings of D.G.**

121. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting government. Submissions made by the various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below.
122. **Product under consideration:** The applicants have alleged that increased imports of Coated Paper and Paper Board into India have caused serious injury to domestic industry and is continuing to threaten serious injury to domestic industry. The domestic industries manufacture Coated Paper and Paper Board made primarily from virgin chemical pulp falling under various headings of chapter heading 4810. The domestic industry has submitted that their products are directly competing products with imported products falling under 48101310, 48101320, 48101330, 48101390, 48101410, 48101420, 48101430, 48101490, 48101910, 48101920, 48101930, 48101990, 48102900, 48103100, 48103200, 48109200 and 48109900 of HSN as well as Customs Tariff Act, 1975. The applicants have alleged serious injury caused to the domestic producer by the increased imports of Coated paper and paperboard made primarily from virgin chemical pulp into India and falling under above headings at eight digit level.
123. Papers and paperboards are made using pulp obtained by chemical or mechanical process or a combination of both. Further the pulp can be obtained either using fresh plant sources or from recycled paper. The present application covers coated paper and paperboard primarily made with virgin pulp using chemical process. The coating may be either on one side or both sides. Blade coating technology is most common for coating these papers and paperboards. The domestic industry has argued that the products falling under the headings mentioned above at eight digit level are same as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. The

products of all these headings find similar uses. Therefore these products are like and directly competing products. Despite possible minor superficial differences, in terms of quality, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses.. Thus the domestic industry has argued that in view of above, for the purposes of safeguard investigation the product basket consisting of products mentioned above needs to be considered as the 'product under consideration'.

124. Some of the interested parties have contended that Coated Paper and Paper Board are distinct products and thus these two cannot be termed as directly competitive to each other. Further, the quality of paper varies in terms of quality. Therefore, it is not appropriate to consider all such products together.

125. The issue has been analyzed. The domestic industry manufactures both Coated Paper and Paper Board. There are imports of both coated paper and paper boards. Further, the coated paper and paper boards are imported in various sizes and these products are also manufactured by domestic industry. There is no evidence produced by the interested parties, which shows that any particular article is imported into India, but the same is not produced by the domestic industry and the imported product does not compete with the product manufactured by the domestic industry.

126. The product under consideration is a group of products. While determining whether the group of imported products is 'like or directly competitive' to the group of products produced by domestic industry or not, it is not necessary to prove that each of the products of the group are 'like or directly competitive' to all the other products of the group. Instead, it is to be seen whether there exists a corresponding 'like or directly competitive' product of each of the imported products.

127. It is observed that the group consists of large number of products of similar nature and similar origin. The imported products falling under these headings at each of the eight digit level are similar as far as their technical characteristics, chemical composition and other basic features are concerned. These products have similar uses. These imported products are directly competing or have potential to compete with such products produced by domestic industry. Despite possible minor superficial differences, in terms of quality, these products have the similar basic physical characteristics and similar end uses. These are sold via similar or identical sales channel. In view of above, the product basket consisting of coated paper and paperboard (as specified above) are the 'product under consideration' for the purposes of safeguard investigation.

128. **Domestic Industry** - The application has been filed by (1) ITC Limited - Paperboards and Specialty Papers Division, 106, Sardar Patel Road, Secunderabad - 500003, Andhra Pradesh, (2) Ballarpur Industries Limited, First India Place, Tower C, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon (Haryana) - 122001 and (3) JK Paper Limited, Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 supported by Indian Paper Manufacturers Association, PHD House, (4th

floor), 4/2 Siri Institutional Area (Opp. Asian Games Village), New Delhi-110 016 for imposition of Safeguard Duty on imports. These three applicants produce nearly 100% of the coated paper and paper board out of virgin chemical pulp. Therefore, these industries constitute domestic industry in terms of clause (b) of subsection (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

129. **Period of Investigation:** The domestic industry has supplied information up to 2008-09 ( up to December) and claimed threat of serious injury based on comparison of 2008-09 (Up to December) with the information of past two years i.e 2007-08 and 2006-07. The preliminary finding was based on 2008-09 (up to December) as period of investigation. The domestic industry has neither relied upon nor submitted data for subsequent period on the ground that the period of investigation should not be extended as it would be against the norm of natural justice. They also contended that the subsequent information is not necessary to be considered as the same might have been influenced by the initiation of Safeguard investigation.
130. The issue has been examined. The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard or the relevant Article XIX of GATT does not specifically define what the Period of Investigation should be. However, the issue of period of investigation has been dealt extensively in the panel's report on Argentina Footwear as well as Appellate Body Report on Argentina Footwear, which are being produced below;

***"Argentina- safeguard measures on imports of Footwear; Report of the Panel***

8.216            *Regarding the investigation's almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the "increased imports" analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse "all relevant factors", and in addition, the situation of the domestic industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions.*



*We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required*

### **Appellate Body Report**

#### **Note 130:**

*The Panel, in footnote 530 to para. 8.166 of the Panel Report, recognizes that the present tense is being used, which it states "would seem to indicate that, whatever the starting-point of an investigation period, it has to end no later than the very recent past." (emphasis added) Here, we disagree with the Panel. We believe that the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past.*

131. From the above it is apparent that neither the Agreement on Safeguard nor the relevant provisions of WTO provide specific definition or interpretation of the period of investigation. The Appellate Body Report has given the finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past. Therefore, the period after filing of the application cannot be ignored in safeguard investigation. However, in order to meet the requirement of natural justice, it is imperative that the information received or collected after initiation of investigation is made accessible to the interested parties. As far as the contention of the domestic industry that it is not necessary to examine the information relating to subsequent period, it is noted that irrespective of the fact whether the examination of information for the period subsequent to initiation of investigation is mandatory or not, the availability of such information certainly helps to have the latest status of domestic industry.
132. However, in the instant case, the domestic industry has not relied on information of the period other than referred to in the application. Therefore, the period of investigation is limited to the period 2008-09 (upto December).
133. **Increased Imports:** The table below gives the imports of product under consideration. The average monthly imports have gone up by 52.59% during April-December, 2009 compared to 2007-08. The average monthly imports had gone up by 124% in 2007-08 compared to 2006-07. Therefore, it is noted that the imports have been increasing since 2006-07.

**Table 1**

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
<b>Total Imports (MT)</b>	106993	132684	151848
<b>Average Monthly Imports (MT)</b>	8916	11057	16872

**134. Value of Imports:** The import price of the product under consideration has increased from US\$655 per MT in 2006-07 to US\$763 in 2007-08 and US\$ 910 in 2008-09. The import price has increased by 19.3% and 16.5% in 2008-09 and 2007-08 respectively compared to their preceding years. Therefore, it is seen that the imports prices are increasing.

**Table 2**

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
<b>Value (USD/MT)</b>	655	763	910

**135. Share of Imports relative to production:** The table below gives imports relative to their production. The share of imports has gone up by 6% during April-December 2008-09, compared to 2007-08.

**Table 3**

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
<b>Share of Imports (%)</b>	30%	33%	39%

**136.** Therefore, it is noted that there is increase in import in quantitative terms as well as in relative term. However, the imports are at higher prices than previous years.

**Serious Injury and Causes Thereof****Statutory framework:**

137. "Serious injury" means as an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry;<sup>1</sup>
138. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.<sup>2</sup>
139. Accordingly, in analyzing serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors, which are relevant, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition, which are relevant to the affected industry, have been considered to evaluate the overall position of the domestic industry.

**Examination of factors:**

140. **Rate of increase of imports:** The rate of increase of imports increased to 52.59% in 2008-09 from 24.01% in 2007-08

**Table 4**

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
Rate of Increase of Imports		24.01%	52.59%

<sup>1</sup> Section 8B(6)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

<sup>2</sup> Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

141. **Market Share of domestic industry taken by imports:** As apparent from the table below, the market share of domestic industry has gone down by 6 % in 2008-09 (April-December). The market share had gone down by 3% in 2007-08 compared to 2006-07.

Table 5

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
Share of domestic industry (%)	70	67	61

142. **Production:** The average monthly production during 2008-09 (April-December) has gone up by 18.81% compared to 2007-08. The production had gone up by 8.14% in 2007-08 compared to 2006-07.

Table 6

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
Total Production (MT)	246664	266751	237699
Average Monthly Production (MT)	20555	22229	26411

143. **Sales:** The average monthly sales during 2008-09 (April-December) have gone up by 18.81% compared to 2007-08. The rise in sales in 2007-08 was 8.14% in 2007-08.

Table 7

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
Total Sales(MT)	252146	264452	236565
Average Monthly Sales (MT)	21012	22038	26285

144. **Capacity Utilization:** The installed capacity of domestic industry increased by 2500 MT/Month during 2007-08 and 2008-09 (up to December). In spite of the increase in installed capacity, the capacity utilization increased in 2008-09 (up to December) to 74% from 67% in 2007-08. This means the domestic industry has been able to increase the production by a quantity, which is more than the expansion of capacity.

Table 8

	2006-07	2007-08	2008-09 (upto December)
Total Installed Capacity(MT)	366000	396000	319500
Installed Capacity (MT/Month)	30500	33000	35500
Capacity Utilization	67	67	74

145. **Employment and Productivity:** The domestic industry has not provided information about their employment and productivity and thus no analysis could be carried out.

146. **Profitability:** The profitability has gone down by 2808.98 in 2007-08 compared to 2006-07 and the ROCE % has gone down from 14.06 % in 2006-07 to 7.34 % in 2007-08 and further to 4.27 % in 2008-09(April to December 2008). The fall in profitability is primarily on account of increased cost of raw material, and depreciation. It has been admitted by the domestic industry that the cost of raw material is higher on account of lack of corporate farming and high energy cost in India. The depreciation is higher in the instant case on account of increased investment on capital goods for capacity expansion. These reasons are not related to increased imports. It is also seen that import prices have gone up over the period and there is no evidence produced by the domestic industry that the increased imports are causing pressure on domestic prices. Therefore, the fall in profitability is not attributable to increase in imports.

Table 9

Year	2006-07	2007-08	2008-09 (upto Dec)
PBT per MT	4187.26	1378.28	317.69
ROCE % (EBIT/Capital Employed)	14.06	7.34	4.27

147. **Evaluation of Overall position of industry:** The domestic industry has expanded their installed capacity in 2007-08 and 2008-09 (up to December). During these periods the production and sales have gone up substantially. The production and sales increased by 18.81% during 2008-09 (up to December) compared to only 8.14% increase in 2007-08. The capacity utilization went up by 7% to reach 74% in 2008-09 from 67% in 2007-08, even after increase in

installed capacity. The production, sales and capacity utilization has been the maximum during 2008-09 (up to December). There has been some fall in profitability, but the domestic industry is still in profit even during recession period. Further, the analysis of fall in profitability shows that the fall is not on account of increased imports.

148. The term 'serious injury' means significant overall impairment in the position of the domestic industry. The profit making domestic industry, which has the maximum production, maximum sales, maximum capacity utilization and has been undertaking capacity expansion during the entire period of consideration, cannot be said to be in the position of significant overall impairment. Further, there is no evidence that the increased imports at higher prices are threatening to cause serious injury to the domestic industry.
149. Therefore, there is no serious injury or threat of serious injury to the domestic industry.
150. As there is no serious injury or threat of serious injury, the question of its causal link with increased imports does not arise.

**Conclusion and Recommendation:**

151. Based on the above, it is concluded that there is no serious injury or threat of serious injury.
152. Accordingly, no safeguard duty on imports of Coated Paper & Paper Board is recommended.

[F.No. D-22011/25/2009]

PRAVEEN MAHAJAN, Director General